



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2019/ कार्तिक 13, 1941

No. 344]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2019/ KARTIKA 13, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2019

[रक्षोपाय शुल्क (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के नियम 5 के अंतर्गत]

(रक्षोपाय जांच)

[मामला सं. (एस जी) 06/2019]

**विषय :** भारत में 'आइसोप्रोपिल एल्कोहल' के आयातों के संबंध में रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच की शुरुआत की सूचना।

**फा. सं. 22/6/2019—डी जी टी आर.**—एक आवेदन मैसर्स दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स कोरपोरेशन लिमि. (इसके पश्चात "डी एफ पी सी एल" अथवा "आवेदक" के रूप में भी संदर्भित) द्वारा समय समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) की धारा 9क के साथ पठित समय समय पर यथासंशोधित रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 (इसके पश्चात "नियमावली" अथवा "मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली" के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में "आइसोप्रोपिल एल्कोहल" (इसके पश्चात "आई पी ए" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" के रूप में भी संदर्भित) के बड़े हुए आयातों जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है का आरोप लगाते हुए दायर किया गया है। उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयातों के कारण हो रही गंभीर क्षति से समान वस्तु अथवा सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी वस्तु का घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने हेतु मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपाय लगाये जाने की मांग की है।

**2. विचाराधीन उत्पाद :** संबंधित उत्पाद "आइसोप्रोपिल एल्कोहल" (आई पी ए) जिसे आइसोप्रोपेनोल के रूप में भी जाना जाता है। आई पी ए रसायनिक सूत्र सीएच<sub>2</sub>सीएचओएचसीएच<sub>3</sub> के साथ एक यौगिक है और इसका उत्पादन ऐसीटोन अथवा प्रोपीलिन का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। यह रंग रहित ज्वलनशील तरल पदार्थ है और इसका उपयोग अनेक औद्योगिक और घरेलू रसायनों, भारी मात्रा में दवा और दवा के फार्मूलेशन, एंटीसेप्टिक, कीटनाशकों और डिटेजेंट आदि के उत्पादन में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में आई पी ए का 99.8 प्रतिशत, जल का 0.1 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशतदोष रहती है। संबद्ध उत्पादों का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में 2905 प्रशुल्क शीर्ष के अंतर्गत कोड 2905 12 20 के अंतर्गत किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त एच एस कोड केवल सांकेतिक हैं और इस उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में लागू रहेगा।

3. **घरेलू उद्योग (डी आई) :** यह आवेदन मैसर्स दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कोरपोरेशन लिमि. द्वारा किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र और तदनुसार विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क की उपधारा (4) के उपनियम (ख) के संबंध में यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है।
4. **जांच की अवधि :** वर्तमान के उद्देश्यों से विचार की गई जांच की अवधि (पी ओ आई) अप्रैल, 2016 से जून, 2019 तक है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि पूर्व की अवधियों और उसके बाद की अवधियों की तुलना में भी अप्रैल, 2018 से जून, 2019 में आयातों ने अचानक, तीव्र और बहुत अधिक उछाल आया है। प्राधिकारी ने “बिल्कुल हाल की अवधि” के रूप में जनवरी-जून, 2019 तक की 6 महीने की अवधि ली है।
5. **बढ़ा हुआ आयात :** आवेदक ने यह दावा किया कि अप्रैल, 2018 से जून, 2019 में स्वतंत्र रूप में तथा घरेलू उत्पादन की तुलना में दोनों में आयातों में अचानक, तीव्र और बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि 2018-2019 में इन आयातों में 2016-2017 की तुलना में 80 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों में वृद्धि प्राथमिक रूप से फिनोल के लिए वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण हुई है, जिसके फलस्वरूप फिनोल का बढ़ा हुआ उत्पादन हुआ है। क्रमिक रूप में इसके फलस्वरूप ऐसिटॉन का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है जो संयुक्त उत्पाद के रूप में उभारता है। इसके फलस्वरूप, ऐसिटॉन की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई है और जिसके कारण ऐसिटॉन आधारित आई पी ए के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अलावा, ऐसिटॉन आधारित आई पी ए की कीमत में तेजी से गिरावट आई जिसके फलस्वरूप इसके आयातों में वृद्धि हुई। इसके अलावा, आवेदक ने अन्य कारकों पर विश्वास किया है जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों के संयंत्रों के बंद होने तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं के फलस्वरूप चीन में संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट तथा यू एस के साथ व्यापार युद्ध के प्रभाव आदि।
6. **घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति का खतरा :** आवेदकों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयातों के कारण आवेदक को गंभीर क्षति हुई है क्योंकि इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इसके बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की उत्पादन की मात्रा, बिक्री की मात्रा, क्षमता का उपयोग और बाजार हिस्से में बहुत अधिक गिरावट आई है। इसके अलावा, बिल्कुल हाल की अवधि में, घरेलू उद्योग इन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री घाटे पर करने के लिए बाध्य हुआ है।
7. आवेदकों द्वारा दायर किये गये आवेदन की जांच करने के बाद, महा निदेशक प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि अप्रैल - दिसंबर 2018 और बिल्कुलहाल की अवधि (जनवरी - जून, 2019) के दौरान ऐसिटॉन की वैश्विक आधिक्य, ऐसिटॉन की गिरती हुई कीमतें, चीन जन. गण. में बढ़ी हुई क्षमताएं और चीन में संबद्ध वस्तुओं के लिए सीमित मांग जैसे अनपेक्षित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि इन आयातों में महोर्मि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और भविष्य में भी गंभीर क्षति का खतरा है।
8. **जांच की शुरुआत :** यह निर्धारित करने के बाद की रक्षोपाय जांच की शुरुआत करने के लिए औचित्य ठहराने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है, महा निदेशक इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या अनपेक्षित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है और क्या इस प्रकार के बड़े हुए आयातों से समान और/ अथवा सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच की शुरुआत करते हैं।
9. सभी हितबद्ध पक्षकार अपने दृष्टिकोण से इस सूचना की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं :

### महा निदेशक

व्यापार उपचार महा निदेशालय (डी जी टी आर)

जीवन तारा बिल्डिंग, चतुर्थ तल,

5, संसद मार्ग,

नई दिल्ली - 110001

10. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी पृथक रूप से पत्र भेजा जा रहा है।
11. इस जांच का कोई अन्य पक्षकार जो एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचार किया जाना चाहता है अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है जिससे कि वह इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर महा निदेशक को पहुंच जाये।
12. यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना पूर्ण नहीं हो तब महा निदेशक अपने जांच परिणामों को अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज कर सकते हैं। इस सूचना को कागज़ी प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

13. **गोपनीय आधार पर सूचना का प्रस्तुतिकरण** : महा निदेशक के समक्ष प्रश्नावली प्रतिक्रिया सहित कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नकसहित) करने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि, जब "गोपनीयता" का दावा उसके किसी भाग के संबंध में किया जाये, वे उस स्थिति में दो अलग अलग सेटों में उसे प्रस्तुत करें। "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इस प्रकार चिह्नित किये बिना करे गये किसी अनुरोध को महा निदेशक द्वारा "अगोपनीय" के रूप में माना जायेगा और महा निदेशक के पास यह स्वतंत्रता होगी कि वे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति दें। दोनों पाठों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां कागज़ी कॉपियों के साथ प्रत्येक के दो (2) सेटों में प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित होगा। गोपनीय पाठ में वे सभी सूचनाएं शामिल रहेंगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/अथवा अन्य सूचना जिसके बारे में इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति गोपनीय के रूप में दावा करते हैं। यह सूचना जिसे गोपनीय प्रकृति के रूप में दावा किया जाता है अथवा वह सूचना जिस पर गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, यह सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे इसके संबंध में दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध करायें कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है। अगोपनीय पाठ, उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है पर निर्भर करते हुए अधिमान्य रूप से सूचीबद्ध अथवा खाली (यदि सूचीबद्ध करना संभव न हो) और संक्षिप्त रूप में, गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए जिससे कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के तथ्यों को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक मामलों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि इस प्रकार की सूचना का संक्षेपण नहीं किया जा सकता है और उसके साथ ही उन कारणों का विवरण कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, महा निदेशक की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महा निदेशक प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि महा निदेशक इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति सूचना को सार्वजनिक करने के लिए अथवा सामान्य या संक्षिप्त रूप में इसे प्रकट करने का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है तब वे इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं। सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिये बिना किया गया कोई अनुरोध महा निदेशक द्वारा रिकार्ड/अभिलेख पर नहीं लिया जायेगा। संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता के लिए आवश्यकता को स्वीकार करने पर महा निदेशक इस प्रकार की सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

14. कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य का अगोपनीय पाठ निहित हो।

15. उस स्थिति में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना दिये जाने से इनकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अर्थपूर्णता से बाधा पहुंचाता है तब महा निदेशक अपने जांच परिणामों को अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को इस प्रकार की सिफारिशें कर सकते हैं जिसे उपयुक्त माना गया हो।

सुनील कुमार, विशेष सचिव एवं महा निदेशक

## DEPARTMENT OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2019

[Under Rule 5 of the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012]

(Safeguard Investigation)

[Case No: (SG) 06/2019]

**Subject:** Notice of initiation of Safeguard (Quantitative Restrictions) Investigation concerning imports of "Isopropyl Alcohol" into India

**F. No. 22/6/2019-DGTR.**—An application has been filed by M/s Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. (hereinafter also referred to as "DFPCL" or the "applicant") in terms of Section 9A of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time,

(hereinafter also referred to as "Act") read with Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "Rules" or "Quantitative Restrictions Rules"), alleging increased imports of "Isopropyl Alcohol" (hereinafter also referred to as "IPA" or "product under consideration" or "subject goods"), which are causing serious injury to the domestic industry. They have sought imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions to protect the domestic industry of like article or directly competitive article from serious injury being caused by the increased imports of the product under consideration.

2. **Product under Consideration:** The product concerned is "Isopropyl Alcohol" (IPA), which is also known as Isopropanol. IPA is a compound with the chemical formula  $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$  and can be produced using Acetone or Propylene. It is a colorless, flammable liquid and is used in production of a variety of industrial and household chemicals, bulk drugs and drug formulations, antiseptics, disinfectants, and detergents etc. The product under consideration consists of 99.8% of IPA, 0.1% of water and 0.1% impurities. The subject products are classifiable under the tariff heading 2905, under code 2905 12 20, in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. It is clarified that the said HS code is indicative only and the product description shall prevail in all circumstances.

3. **Domestic Industry (DI):** The application has been filed by M/s Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. The applicant is the sole producer of the subject goods in India and accordingly, constitutes domestic industry as defined in terms of Clause (b) of the sub-section (4) of Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

4. **Period of Investigation:** The period of investigation (POI) considered for the purposes of present investigation is from April-2016 to June-2019. The applicant has submitted that there has been a sudden, sharp and significant surge in imports in April, 18 to June, 2019, as compared to the earlier periods and thereafter as well. The Authority has taken six months' period from January-June, 19 as the 'most recent period'.

5. **Increased Imports:** The applicant claimed that there is a sudden, sharp and significant increase in imports in April, 18 to June, 19, both in absolute terms as well as relative to domestic production. It is noted that the imports in 2018-19 have increased by more than 80%, as compared to that in 2016-17. The applicant has claimed that the imports have increased primarily due to an increase in global demand for phenol, which led to an increased production of Phenol. This in turn, resulted in a surplus production of Acetone, which emerges as a joint product. As a result, the prices of Acetone plummeted, and led to an increased production of Acetone-based IPA. Further, the price of Acetone-based IPA declined sharply, leading to increased imports. The applicant has further relied on other factors such as declining demand of subject goods in China as a result of shut down of plants for downstream products, due to environmental concerns, as well as impact of trade war with US etc.

6. **Serious Injury and threat of serious injury to the domestic industry:** The applicants have claimed that the increased imports of product under consideration have caused serious injury to the applicant as the imports are undercutting the prices of the domestic industry and have taken over its market share. As a result, the production quantity, sales quantity, capacity utilization and market share of the domestic industry etc. have fallen considerably. Further, in the most recent period, the domestic industry has been forced to sell the subject goods at losses.

7. After examining the application filed by applicants, the Director General, prima facie, finds that there is a significant increase in imports of subject goods during Apr-Dec, 2018 and the most recent period (Jan-Jun, 2019) as a result of unforeseen developments such as global surplus of Acetone, declining prices of Acetone, increased capacities in China PR and limited demand for the subject goods in China. The Authority prima facie finds that the surge in imports have caused serious injury to domestic industry and also poses threat of serious injury.

8. **Initiation:** After determining that there is sufficient evidence to justify initiation of safeguard investigation, the Director General initiates an investigation pursuant to Rule 5 of the Quantitative Restrictions Rules in order to determine whether there have been increased imports as a result of unforeseen developments, and whether such increased imports have caused serious injury to the domestic industry of like and/or directly competing products.

9. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

**Director General**  
**Directorate General of Trade Remedies (DGTR),**  
**Jeevan Tara Building, 4th Floor,**  
**5, Parliament Street,**  
**New Delhi -110001**

10. All known interested parties are also being addressed separately.
11. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General on aforementioned address within 30 days from the date of this notice.
12. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director General may record its findings on the basis of the facts available on record. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
13. **Submission of Information on Confidential Basis :** The parties making any submission (including Appendices/ Annexure attached thereto), before the Director General including Questionnaire Response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Director General and the Director General shall be at a liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Director General. The Director General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director General. The Director General on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
14. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
15. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Special Secy. & Director General